



क्षेत्र पाकिस्तान में कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों की मौत का विरोध करते हुए शिया हजारा समुदाय के लोग।

ब्रिटेन में कोरोना के कारण लॉकडाउन और कड़ा किया जा सकता है : जॉनसन

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान प्रतिवर्धनों को और कड़ा किया जा सकता है क्योंकि देश कोरोना वायरस के नए प्रारूप (ट्रेन) से सहमत है। हमें कई कड़े उपाय करने होंगे। वर्तमान नियमों के तहत संचालन कुछ हफ्ते के लिए देश भर में सभी स्कूलों के बढ़करने की अपील कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि अधिकावक्तों को अपने बच्चों को उन इलाकों के स्कूलों में भेजना चाहिए जहाँ वे खुले हुए हैं क्योंकि खतरनाक वायरस से बच्चों को खतरा काफी कम है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आगामी हफ्तों में लोगों के लिए कड़े प्रतिवर्ध लगाए जा सकते हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इस सप्ताहांत 57,725 की वृद्धि हुई वहीं मृतकों की कुल

मृत सागर में ड्रिलिंग के दौरान खतरनाक संकेत, इजरायल में आ सकता है खतरनाक भूकंप

लंदन, (एजेंसी)। इजरायल के वैज्ञानिकों को मृत सागर में ड्रिलिंग के दौरान खतरनाक संकेत मिले हैं। उन्हें फॉल्ट लाइन पर तनाव दिखा है, इससे आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले सालों में यहां भूकंप आ सकता है। धरती की बाहरी सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण ये फॉल्ट लाइन पैदा होती हैं। तब अवीव यनिवर्सिटी की टीम का कहना है कि भूकंप आने पर सिकड़ों लोगों की जान जा सकती है। हालांकि, यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि वह भूकंप कब आएगा।

टीम का कहना है कि यहां रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है जिससे कमज़ोर इमारतें गिर से और मरम्भूत इमारतों को नुकसान की आशंका है। रिसर्च में पता चला है कि हर बदल जाने से तलचट जमा होता है।

120-150 साल के अंतराल पर भूकंप आते ही हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह 10 साल के अंदर हो जाएगा। पिछ्ली बार 6.2 का भूकंप डेंग सी में 1927 में आया था जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसका असर जॉर्डन, जेरूसलम, बेथलेहम और जापान में देखा गया था। डेंग सी सीरिया-अफ्रीका रिप्ट के पास स्थित है।

रिसर्चर्स ने डेंग सी में कई सी मीटर तक ड्रिलिंग कर धरती की सतह को स्टॉप किया है जिससे पता चल सके कि पिछले 2.2 लाख साल में कब-कब भूकंप आए हैं। हासिल होने वाले लोगों में तैयार का बाद गर्मियों में पानी भाप में बदल जाने से तलचट जमा होता है।

अभिभावक की स्वीकृति के बिना भी नाम बदल सकती है महिलाएं

रियाद, (एजेंसी)। महिलाओं के लिए बहेतर सख्त कानूनों वाला इसलामी देश सऊदी अरब में तेजी से स्थिति में बदलाव कर आ रहा है। हालिया बदलाव के तहत महिलाओं को वह अधिकार दिया गया है कि वे अपने अभिभावक की स्वीकृति के बिना भी नाम में बदलाव कर सकती हैं। पहले इसके लिए घरवालों की इजाजत जरूरी थी। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने रिवावार को इसकी जानकारी दी। नए कानून के तहत अब सऊदी अरब में कई महिला या पुरुष नाम सहित खुद से जुड़े अहम डेटा में बदलाव करा सकता है। पहले सिर्फ पुरुषों को अधिकार था कि वे घर के गार्जिन की अनुमति के बिना ऐसा कर सकें। अब यह अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया है। सऊदी अरब ने देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शिअन जिआनहुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूजुगों लोगों का कलब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तांशक्ति सप्ताह के प्रवक्ता ने काम करते हुए लोगों में देखे गए हैं।

जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया। अब जैक को फैनल के हिस्सा नहीं है।

इसके बाद जैक मा के दुर्दिन शुरू हो गए और उनके बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिवर्ध लगाया जाना शुरू कर दिया गया। नवंबर महीने में चीनी अधिकारियों ने जैक मा को जोरदार झटका दिया और उनके एंट ग्रुप के 37 अब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद करने का आदेश सीधी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के कारण आदेश दिया गया था। इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्ण संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूजुगों लोगों का कलब करार दिया गया। चीन के एक अन्य अरबपति शिअन जिआनहुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है।

जैक मा सिद्धायल के विवाद के कारण अब जैक को फैनल के हिस्सा नहीं है।

हालांकि इस शो के फाइनल से कई सालों पहले ही जैक मा ने ट्रॉफी करके कहा था कि वह नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद से उनके तीन ट्रॉफी के अंतर्गत से कोई पोस्ट नहीं किया गया है। इसके पहले वह लगातार द्वौट करते रहते थे। चीन में आवाज को दबाए जाने वाले जैक मा पहले ऐसे शख्स नहीं हैं। चीन बड़ी संख्या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्ण संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूजुगों लोगों का कलब करार दिया गया। चीन के एक अन्य अरबपति शिअन जिआनहुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है।

जैक मा सिद्धायल के विवाद के कारण अब जैक को फैनल के हिस्सा नहीं है।

हालांकि इस शो के फाइनल से कई सालों पहले ही जैक मा ने ट्रॉफी करके कहा था कि वह नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद से उनके तीन ट्रॉफी के अंतर्गत से कोई पोस्ट नहीं किया गया है। इसके पहले वह लगातार द्वौट करते रहते थे। चीन में आवाज को दबाए जाने वाले जैक मा पहले ऐसे शख्स नहीं हैं। चीन बड़ी संख्या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्ण संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूजुगों लोगों का कलब करार दिया गया। चीन के एक अन्य अरबपति शिअन जिआनहुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है।

जैक मा सिद्धायल के विवाद के कारण अब जैक को फैनल के हिस्सा नहीं है।

हालांकि इस शो के फाइनल से कई सालों पहले ही जैक मा ने ट्रॉफी करके कहा था कि वह नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद से उनके तीन ट्रॉफी के अंतर्गत से कोई पोस्ट नहीं किया गया है। इसके पहले वह लगातार द्वौट करते रहते थे। चीन में आवाज को दबाए जाने वाले जैक मा पहले ऐसे शख्स नहीं हैं। चीन बड़ी संख्या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्ण संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूजुगों लोगों का कलब करार दिया गया। चीन के एक अन्य अरबपति शिअन जिआनहुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है।

जैक मा सिद्धायल के विवाद के कारण अब जैक को फैनल के हिस्सा नहीं है।

हालांकि इस शो के फाइनल से कई सालों पहले ही जैक मा ने ट्रॉफी करके कहा था कि वह नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद से उनके तीन ट्रॉफी के अंतर्गत से कोई पोस्ट नहीं किया गया है। इसके पहले वह लगातार द्वौट करते रहते थे। चीन में आवाज को दबाए जाने वाले जैक मा पहले ऐसे शख्स नहीं हैं। चीन बड़ी संख्या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्ण संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है।

इसके बाद जैक मा आने टीवी शो अप्रीली बिजनेस हाईरोज से नवंबर में फाइनल से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं नहीं शो से उनकी तस्वीर को भूज

संपादकीय

बीतता दशक और आगे की चिंता

पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है 2020 के खत्म होने का। मानो, उस साल के जाते ही वे सारी मुसीबतें टल जाएंगी, जो इस वर्ष हमारे सिर पर आ पड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ा संकट है, कोरोना महामारी और उससे बढ़ा हुई तमाम तरह की आर्थिक-सामाजिक महामारियाँ। हालांकि, कोरोना वाला पहला मामला 2019 में ही चीन में सामने आ चुका था, पर वह साल भी बस नाम के लिए इसके साथ है। इसका प्रचंड रूप और पूरी दुनिया में सका प्रकोप तो 2020 ने ही देखा। शुरू में कहा गया कि यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा झटका है। लेकिन बहुत जल्द ही साफ हो गया कि यह कहीं बड़ा संकट है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। विश्व बैंक ने माल के पूर्वार्द्ध में ही चेतावनी दे दी कि इस साल पूरी दुनिया की जीड़ीपी में 5.2% कम से कम 5.2% प्रतिशत की गिरावट आने का खतरा है। वित्त वर्ष की अंतिम हली तिमाही में भारत की जीड़ीपी में 24.9% फीसदी की गिरावट दर्ज भी हो गई थी। ये झटके आने अभी बढ़ नहीं हुए हैं। मार्च-अप्रैल की तेज गिरावट के बाद से अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों में कुछ-कुछ सुधार के अंकेत दिख रहे हैं। थोड़ी खुशखबरी भी आती है, लेकिन फिर बड़ी भासंका दिखने लगती है। अभी अक्टूबर तक हाल सुधार रहा था, लेकिन नवंबर ने फिर हाल बिगाड़ दिया। सीएमआई के कंज्यूमर सर्वे में दिखता था कि नवंबर में रोजगार के अंकड़े में लगभग 0.9% प्रतिशत की गिरावट भारी और भारत में सिर्फ 4.3% फीसदी लोग ऐसे थे, जिनकी आमदनी प्रेष्ठले साल के इसी महीने के मुकाबले बड़ी है। बिजनेस अखबार मिंट के 'इमर्जिंग इकोनोमी ट्रैकर' में दिख रहा है कि नवंबर में भारत उम्पते हुए देशों या विकासशील देशों की कतार में भी सबसे नीचे पहुंच गया है। यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े हिस्से की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि जब कोरोना खत्म होने लगें, तब हमारी अर्थव्यवस्था उन गिने-चुने देशों में होगी, जिन्हें इसके बाद तेजी से बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां भारत का नाम हमेशा चीन के साथ लिया जा रहा था, लेकिन अब नजारा दिख रहा है, वह परेशान करने वाला है। नवंबर में बीन से निर्यात 21% प्रतिशत बढ़ा है। लगातार छह महीने से वहां बढ़त दिख ही ही है, जबकि भारत से निर्यात में 8.7% प्रतिशत की गिरावट आई है। अप्रैल महीने में 60 फीसदी गिरने के बाद से सिर्फ सिंतंबर का महीना ऐसा रहा, जब यहां छह फीसदी की बढ़त दिखी। इस साल की शुरुआत में सबसे बड़ी चिंता थी, आर्थिक तरक्की की रफ्तार। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सरकार ग्रोथ को वापस पट्टी पर लाने के लिए कुछ कर पाएगी? अब वह सवाल और बड़ा हो चुका है और चिंता भी। ऐसे में, दस साल पहले नैटिकर देखना बुरा नहीं होगा। ठीक दस साल पहले प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री थे और 2011-12 के बजट में उन्होंने यह उम्मीद जताई थी कि अगले साल देश की जीड़ीपी नौ प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगी। वह साल इसलिए भी याद रखना चाहिए कि उस बक्त भी अर्थव्यवस्था एक प्रणेश सकट से बाहर निकली ही थी। यह था 2008 का विश्वायापी आर्थिक झटक। रिजर्व बैंक के कड़े नियमों और गवर्नर वाई वी रेझै के अनुशासित विवैये की बजह से भारत इस सकट का सीधा शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन जाकी दुनिया का इतना असर जरूर आया कि देश के व्यापारियों को तरह-तरह के सहरों की जरूरत पड़ गई। प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार अब वे सहरों हटाने लगी है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि खाने-पीने की चीजों की महांगाई दर 20.2% प्रतिशत से गिरकर 10.3% प्रतिशत पर पहुंच गई है। हालांकि यह भी कम नहीं था, लेकिन उस साल देश की ग्रोथ बड़ाने में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी बजट में प्रणब मुखर्जी ने केरोसिन, रसोई गैस और खाद पर सब्सिडी के डायरेक्ट औपसकर के लिए टास्क फोर्स बनाने का एलान किया। दस साल में इतना ही हासिल हो गया है कि अब सब्सिडी को सीधे खातों में हस्तांतरित किया जाता है। इसी साल अक्टूबर तक 47 करोड़ लोगों को इस रास्ते 1,41,714 करोड़ रुपये की रकम उनके खातों में पहुंचाई गई। लेकिन क्या दस साल पहले जो चिंताएं देश के सामने थीं, उन सबके बारे में यही कहा जा सकता है? साल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें शायद अब कभी नहीं जाएंगी। मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना, शारीरिक दूरी का पालन और 'वर्क फ्रॉम होम होगा'। अपापा में अवसर का सबसे बड़ा उदाहरण तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। उसने न सिर्फ काम करने का अंदाज बदल दिया, बल्कि ज्यादातर यारों का नक्शा भी। आने वाले समय में बिल्डरों और आकिटेक्टों के नामने शायद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उनके बनाए घर वर्क फ्रॉम ग्रोम के लिए किनते मुफीद होंगे हाल ही में गार्टनर के एक सर्वे से पता चलता है कि 41 फीसदी लोग तो महामारी खत्म होने के बाद भी काफी ममत्य तक घर से ही काम करने वाले हैं। यह बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे नाखोंचों लोगों के लिए, जो मजबूरी में महानगरों के छोटे-छोटे घरों में जिंदगी बेता रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोज दफ्तर जाना होता है। ऐसे लोगों के लिए भी, जो अपने गांव, कस्बे या छोटे शहर के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते, क्योंकि नौकरी कहीं और है। लेकिन साथ में यह एक नई चिंता बढ़ा करता है। घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन सब कुछ घर में ही हो जाएगा, तो इंसान बाहर क्यों निकलेगा और इंसान बाहर नहीं निकलेगा, तो कूल, कॉलेज और दफ्तर में बनने वाले रिश्तों और सामाजिक समीकरणों का क्या होगा आर्थिक मोर्चे पर दस साल पहले जो सबसे बड़ी चिंता थी, कमोबेश आज भी वही है। देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज करना। इसके साथ जड़े सवाल भी बहुत हिले-डुले नहीं हैं। तरक्की में सबकी गणितीय कैसे हो? अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जो बड़ा खर्च करना है, उसका इंतजाम कैसे हो? सरकार की कमाई बढ़े और खर्च घटे, सके लिए क्या-क्या करना है? इन सवालों के जवाब तलाशने के साथ न-नसे बड़ा और जरूरी सवाल है कि समाज में विद्रोष और असंतोष कैसे नम किया जाए, क्योंकि यह तरक्की की सबसे जरूरी शर्त है।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ

विदेश नीति में ‘आइलैंड डिप्लोमेसी’ का महत्व, जानिए क्या है भारतीय कृटनीति का स्तंभ

संयुक्त राष्ट्र महासभा के
74वें सत्र के आयोजन के
दौरान 24 सितंबर, 2019
को इंडिया पैसिफिक
आइलैंड्स लीडर्स मीटिंग
का आयोजन न्यूयॉर्क में
किया गया था। भारत के
प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ
संबंधों में एक ईस्ट
पॉलिसी के बाद मजबूती
आई है। भारत ने पैसिफिक
द्वीपों में अपने
विकासात्मक एजेंडे को
मजबूती दी है। इस बैठक
में फिपिक देशों ने सतत
विकास लक्ष्यों की प्राप्ति,
नवीकरणीय ऊर्जा के
सहयोग को बढ़ावा देने,
हाल ही में गठित ग्लोबल
कोलिशन ऑन डिजास्टर
रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में
शामिल होने और क्षमता
निर्माण हेतु सहयोग करने
पर चर्चा की।

हिंद महासागर के द्वीपीय देशों से भारत की पहुंच के प्रयासों के लिए कई सामरिक उद्देश्य काम कर रहा है। इनमें से एक भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हालिया श्रीमती व अन्य सेशेल्स की यात्रा इसी सोच के एक हिस्सा रही है और इस रूप से द्वीपीय कट्टनीति (आइएडिलोमेसी) को भारतीय विदेश के स्तंभ के रूप में विकसित के प्रयास किए जा रहे हैं। सेशेल्स एजमेसन द्वारा ये में भारत अपने अहंकार की स्थापना के अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही अन्य द्वीपीय देशों अपनी आर्थिक कट्टनीतिक संलग्नता को भी बढ़ा रहा है। इसी क्रम में ही में भारत के विदेश मंत्रलय इंडो पैसिफिक डिवीजन के गठन साथ ही द्वीपीय कट्टनीति औपचारिक रूप दे दिया गया पिछले वर्ष भी भारत सरकार ने नए इंडियन ओसियन रीजन डिवीजन के गठन के साथ ही आई-डिलोमेसी की नींव रख दी थी। इस वर्ष ठोस रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस अंतर्गत श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स को एक साथ शामिल किया गया था और वर्ष 2019 में डिवीजन में विस्तार कर मेडागास्कर, कोमोरोस और रीयूनियन द्वारा व्यवस्थापन कर दिया था। रीयूनियन पर फ्रांस का स्वामित्व है और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अध्यक्षता में आयोजित ईरान ओसियन रिम एसोसिएशन काउंसिल 10 अफ मिनिस्टर्स वर्चुअल बैठक में भारत के साथ फ्रांस को इस एसोसिएशन का 23वां सदस्य बनाया गया है। भारत के द्वीपीय सुरक्षा और विभिन्न देशों को मजबूती देने वाला दमना गया है।



राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री ने सेशेल्स की यात्रा की थी और तीन दशकों में किसी भारतीय नेता श्रीलंका के हंबनटोटा, अफ़्रीका के जिबूती और सेशेल्स में अपने अड्डे बना रखे हैं। वहाँ अमेरिका ने जिबूती

जगजोड़ कर भारत विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन (फिपिक) इसी प्रकार का संगठन है जिसका गठन विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्थितता, समुद्री डकौती से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से द्वीपों के अस्तित्व पर बढ़ता खतरा, मत्स्य और अन्य संसाधनों की होड़, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव से समुद्री जैवविविधता का क्षरण, प्रवाल भित्ति से बने द्वीपों पर बढ़ रहे खतरों से निपटने के दृष्टिकोण से फिपिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका गठन भारत के नेतृत्व में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए 2014 में किया गया था। इसे भारत की आइलैंड डिलोमेसी के एक मजबूत उपकरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 14 देश हैं जिसमें भारत को छोड़ सभी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं। इस संगठन के देश यद्यपि सार्थक रूप से छोड़े भू क्षेत्र वाले देश हैं, लेकिन इनका आर्थिक क्षेत्र व्यापक है। इस कारण भारत इनके साथ मिलकर महासागरीय अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनामी के विकास के लिए कार्य कर सकता है। भारत की प्रशांत क्षेत्र में संलग्नता बढ़ाने के लिए इसे प्रधानमंत्री की महासागरीय कूटनीति के रूप में भी देखा गया है।

वर्ष 2014-15 में प्रशांत द्वीपीय देशों और भारत के मध्य व्यापक स्तर पर कुल व्यापार 30 करोड़ डॉलर का था जिसमें से भारत का इन देशों में निर्यात 20 करोड़ डॉलर और आयात

10 करोड़ डॉलर का था। वर्ष 2014 में इस संगठन के गठन के समय भारत ने इन देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन व स्वच्छ ऊर्जा संवर्धन हेतु 10 लाख डॉलर की राशि वाले विशेष कोष का गठन करने और भारत में इन देशों के लिए व्यापार कार्यालय खोलने पर बल दिया था। शासनाध्यक्षों के स्तर पर दूसरे समिट में फिपिक सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधार और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का मजबूत समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में फिजी में एक मैटिकल सेंटर गठित करने, वहां एक फार्मस्युटिकल प्लांट का निर्माण करने और फिजी के पर्यटन क्षेत्र में भारतीय निवेश करने की अपेक्षा को पूरा करने पर बल दिया था। भारत ने समिट में पापुआ न्यू गिनी में अवसरंचात्मक क्षेत्र को विकसित करने, सड़कों, राजमार्गों, एयरपोर्ट्स आदि बनाने में सहयोग की बात की।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के आयोजन के दौरान 24 सितंबर, 2019 को इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स लीडर्स मीटिंग का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। भारत के प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ संबंधों में एकट इस्ट पॉलिसी के बाद मजबूती आई है। भारत ने पैसिफिक द्वीपों में अपने विकासात्मक एजेंडे को मजबूती दी है। इस बैठक में फिपिक देशों ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग को बढ़ावा देने, हाल ही में गठित ग्लोबल कोलिशन ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने और क्षमता निर्माण हेतु सहयोग करने पर चर्चा की।

नए कृषि कानूनों से बहुरेंगे किसानों के दिन, केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से खेती में हो रहा तेजी से सुधार

मैं अर्थासांस्री हूं और न ही विज्ञानी। मैं कृषक और शिक्षक भी नहीं हूं मैं हूं एक मजदूर, लेकिन पिछले 40 वर्षों से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने देखा और समझा है कि भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए गांव-गरीब-किसान की जिंदगी में खुशहाली तथा विकास की नई सुवध का प्रस्फुटन आवश्यक है। केंद्र सरकार गांव-देहात, खेत-खलिहान और किसानों-मजदूरों के घरों में विकास की ऐसी रोशनी पहुंचाने के लिए 'अहर्निश सेवामहे' यानी दिन-रात सेवा संकल्प के साथ काम कर रही है। कृषि हमारे देश की आत्मा है। कृषि ही हमारी संस्कृति एवं परंपरा का आधार है। हमारे त्योहार, रीत-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन और उपासना पद्धतियों की जड़ें भी गांव-देहात तथा खेतों में ही समाई हुई हैं। कहने को तो भारत गांवों-किसानों का देश है, लेकिन किसानों और ग्रामीणों की सेहत-सीरत और सूरत बदलने के लिए आजादी के बाद कुछ खास नहीं किया गया। आजादी के समय देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था जो अब घटकर 20 फीसद से नीचे आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सत्ताधीश और दुक्मरान कागज के खेतों पर कलम के हल चलाते रहे, स्याही से सिंचाई करते रहे, आशासनों के उर्वरक डालते रहे, किसान यूरिया के लिए लाठियां खाते रहे और नेता आंकड़ों की फसलें कटकर किसानों को भरमाते रहे। यदि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार पहले ही हो गए होते तो आज किसानों की स्थिति कहीं बेहतर होती।

केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से गांव-गरीब और किसानों के हालात तेजी से बदल रहे हैं। हमारे ग्राम्यों परामर्शी दे रहे मैट्रिक्स दिया है कि

बदलाव अब एक सामूहिक पूर्ति की बुनियादी शर्त है। नए कृषि कानूनों के बाद बिचौलियों के नागपाश से बचा वे अपनी उपज अपनी शर्तों पर कहीं भी बैच सकेंगे। यह ही है। स्थानीय मंडियां दलालों, जिनमें थीं, लेकिन अब कृषि विधीगिक उत्पादों की तरह एक अवधारणा से जुड़ जाएगी। निवेश बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा वयस्था मजबूत होगी और देश में कृषि क्षेत्र का योगदान ही हुई तो देश ठीक नहीं होगा, व सून।

किसानों को अपनी उपज देश के लिए निर्बाध अवसर और आवश्यकता। किसानों को न तो कोई ही माल दुलाई का खर्च। मुमाम व्यापार के लिए ई-ट्रेडिंग। किसान खरीदारों से सीधे रूप दलाल और बिचौलिये उन्हें मिलने वाला कमीशन गली कीमत से जुड़ जाएगा।

दिन में स्थानीय स्तर पर के साथ ही किसानों को तीन वयस्था भी की गई है। इसके अद्वितीयों के संरक्षण की भी पूरी तरीकों में की गई है। बावजूद इसके विवरणसंतोषी विपक्षी दलों तथा लूट रहे दलालों के बहकावे परिणत कृषिकलन अधिनेतर कर्प रखे हैं। कोई आंदोलनकारी किसान नेता या विपक्ष का कोई नेता बुद्धार्थ यह नहीं कह पा रहा है कि कानूनों के किस प्रावधान से किसानों का नुकसान होगा।

वहीं इन किसानों को उकसाने वाले विपक्षी दलों के झूठ और दुष्प्रचार पर भी गैर किया जाए। विपक्ष कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी। यह बात कानून में कहा लिखी है? फिर जब तक देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू है और जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की दुकानें चल रही हैं तब तक एमएसपी पर सरकारी खरीद बंद कैसे हो जाएगी? दूसरा झूठ यह है कि किसान बाहर उज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार कह रही है कि मंडियां रहेंगी। किसान को जहां उपयुक्त कीमत मिले वह वहां अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के अलावा आंदोलनरत किसान नेता राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत जीवन भर किसानों को मंडियों की धेराबंदी से मुक्त कराने की मांग करते रहे, पर उनकी बात सुनी नहीं गई। अब मोदी जी ने इसे स्वीकार किया है तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खालिस्तानी झंडे भी लहराए जा रहे हैं। देश विरोधी कार्यों में सलिस रहे तत्वों और दिल्ली दंगों के अभियुक्तों की रिहाई की मांग की जा रही है। इसका किसानों और कृषि कानूनों से क्या लेना देना है?

एक झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि अनुबंध खेती के चलते किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन कानून में तो जमीन का उल्लेख ही नहीं है। अनुबंध तो सिर्फ उपज का होगा। जो सरकार साल दर साल कृषि उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसे बेच गाना कर सकती है।

नया जज्बा, नई उम्मीद

साल 2020 जाते-जाते जो समस्याएं 2021 के हाथों में थमाता गया है, उनमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उलझनों सुलझने की ओर जाती दिख रही हैं। पहला है किसान आदोलन। साल खत्म होने के दो दिन पहले किसान नेतृत्व और सरकार के बीच बातचीत में कुछ सहमतियां हासिल कर ली गईं। उम्मीद है कि आगामी चार जनवरी को होने वाली मुलाकात में दोनों पक्ष ठोस नितीजे पर पहुंचेंगे और करीब डेढ़ महीने से दिल्ली के आसपास सड़कों पर बैठे किसान संतुष्ट होकर अपने खेतों की ओर लौट जाएंगे। दूसरी समस्या है कोरोना महामारी, जिसमें प्रतिदिन होने वाले नए संक्रमणों की संख्या साल के खत्म होते-होते काफी कम हो गई थी। इसके अलावा वैक्सीन बन जाने की खबरों ने भी लोगों में उम्मीद भरी है। लेकिन ये उम्मीदें पूरी करने के लिए नए साल को कुछ वक्त देना होगा। अभी तो टीके के असर और इसके साइड इफेक्ट्स बौरह को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है। वायरस का रूपांतरण एक अलग ही मसला है।

जाहिर है, इस महामारी से तुरत-फुरत छुटकारा नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका जो आतक सबके दिलों में बैठ गया है, उससे मुक्त मिल जाए तो यह भी कुछ कम बड़ी बात नहीं होगी। खौफ का यह साया हटने के बाद ही स्पष्ट होगा कि जो दूसरी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं वे दरअसल कितनी गंभीर हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग गांव चले जाने के कारण या फैक्ट्रियां-कोराबार जैसे घटनाएँ होती हैं, वे भी

हैं, उनमें से कितने सचमुच बेरोजगार हो चुके हैं, यह तब पता चलेगा जब उनके कार्यस्थलों में दोबारा काम शुरू हो जाएगा और उनमें जितनों को खपना है वे खप जाएंगे। बाकी बचे लोगों के लिए कामकाज का इंतजाम करने के बारे में तभी सोचा जा सकेगा। यह नए साल की सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि लोगों का कामधृष्टि शुरू होने से ही अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी, जिससे विकास की बंद पड़ी गड़ी को कुछ गति मिल पाएगी। साल 2020 अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए भी याद किया जाएगा।

इस पर सुधीरम कोर्ट का फैसला तो 2019 के आखिर में आ गया था, लेकिन उस फैसले के मुताबिक मंदिर और मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया 2020 में ही आगे बढ़ी। बहरहाल, मंदिर के लिए झाड़ा लेकर चदा वसूली करने और उस क्रम में अशांति भड़कने की जो खबरें मध्य प्रदेश से पिछले दिनों आईं, वे परेशान करने वाली हैं। उनसे यह आशंका पनपती है कि क्या यह विवाद समाज में अशांति पैदा करने का जरिया आगे भी बना रहेगा? बेहतर होगा कि इस लंबे विवाद की सुखद परिणति के बाद इसे नए-नए बवाल कटाने का सबब न बनाया जाए। बहरहाल, चिंता और सोच-विचार के ओर भी कई मुद्दे हैं, लेकिन नए साल के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही होगी कि वह 2020 से मिली विरासत में ही उलझा रह जाता है या नई उपलब्धियों के बल पर अपनी स्वतंत्र पहचान

यूपी में नई सियासी हलचल के संकेत, ओवैसी के आने से सुहेलदेव और अन्य छोटी पार्टियों को हो सकता है नुकसान

क्या गरीब वर्ग सिर्फ बोट पाने तक ही सीमित है गरीब के लिए चलाई जाने वाली जन आहार योजना तो चलाई ही जा सकती है। क्या पता आप दोबारा सत्ता में आ जाएं, कम से कम गरीब को रोटी तो मिलती रहे। दरअसल हमारे देश में मुंशी प्रेमचंद का गरीब जो आज भी हमारे समाज का बड़ा तबका है, उसे बोट बैंक की सेहत के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है, पर सिर्फ बोट पाने तक ही क्यों क्या उस थाली को सत्ता के मोह से आगे उसकी पौष्टिकता और जरूरत के लिए निरंतर नहीं चलाया जा सकता सियासत की रोटियां तो सिकती ही रहती हैं, गरीब के पास तो सिर्फ

जिसकी कुर्सी, उसकी थाली... सत्ता बदलते ही बदल जाता है गरीबों के निवाले का स्वाद आप सोच रहे होंगे कि भला ये कुर्सी के साथ थाली का क्या मेल बिलकुल है। दरअसल जब भी, जिस राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो सियासत के बैनर, पर्दे बदलने के साथ चौक-चौराहों पर लगी गरीब की थाली के रंग भी तो बदल जाते हैं। ब्रांड नेम और थाली के जायके पर सत्ता पार्टी का स्वाद चढ़ जाता है। अब गरीब को क्या है खाने में दाल-भात मिले या सब्जी-रोटी, वडा पाव मिले या दाल मस्खी, खिचड़ी मिले या इडली या फिर दही-चावल। इस पर भी सवाल उठाना उसके ओहरे की बात थोड़ी है कि ये थाली दो-चार दिन मिले, महीने मिले या कुछ साल मिलते-मिलते कब विलमुस हो जाएँ पूर्णी दिल्ली के एक इलाके में स्थानीय सांसद गौतम गंभीर ने भी ऐसी ही सस्ती थाली की सेवा शुरू की है, जिसके बाद से यह विषय एक बार फिर सुर्खियों में है। एक और चीज देखिए। इस थाली में जायके और पौष्टिकता की भले आपको खुशबू नहीं आए, लेकिन हाँ, जिस राज्य में गरीब के नाम की थाली जन्म लेगी, उसमें फलेवर उस राज्य का ही होगा।

एक रोचक चीज और देखिए। जिस तरह किसी हवेली की कीमत को लेकर बोली लगती है कि उससे ज्यादा मुझसे लो, मैं तुम सबसे ज्यादा कीमत लगाता हूँ। लेकिन यहाँ सियासत वाले गरीब की थाली पर जरा विपरीत बोली लगते हैं, मैं तमसे



किसी ने दस रुपये में रोटी खिलाई, किसी ने आठ रुपये में, कोई पांच रुपये में, तो कोई एक रुपया, तो किसी ने मुफ्त में ही रोटी खिलाने की दावेदारी ठोक दी।

सत्ताधारी को तो इस तबके के समक्ष अपनी मौजूदगी रखनी होती है और भला रोटी यानी भूख से बड़ा बोट पाने का रास्ता और क्या हो सकता है। इन योजनाओं के शुरू होने के बाद संचालन तो एनजीओ द्वारा कराया जाता है। एनजीओ को ठेका मिला, कुछ दिन चौक-चौहाहे पर गरीब बस्ती के

भासपास खाना बंटा, फिर तलाशते रहिए। न देखेंगा डेला और न ही बटेंगा खाना। इसी तरह इन आलियों की योजनाओं के नामकरण में भी सत्ता की दुर्र होगी। यहां एक बड़ा सवाल यह भी जेहन में ठाठौंती है कि जिसे ही सत्ता में दल बदल होता है वो ये थाली क्यों बदं हो जाती है। इस थाली और कुर्सी की शुरुआत भी बहुत दलचस्प रही है जिसे तमिलनाडु की पूर्व प्रधानमंत्री जयललिता ने वर्ष 2013 में दक्षिण के शाहर व्यंजनों के साथ तीन से पांच रुपये की

कीमत में शुरू किया था। मजे की बात देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2016 में इनी थाली ने उन्हें दोबारा सत्ता में भी ला दिया। फिर क्या था, यहीं से यह थाली विभिन्न राज्यों में जायकों की खुशबू फैलाती गई, राजनीतिक पार्टियों ने इसे हाथों-हाथ लिया। दिल्ली में 2015 तक सत्ता में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जन आहार योजना चलती थी, गरीब को खाना मिलता था। सत्ता गई तो गरीब की रोटी भी गई। वह भी उस दिल्ली में जिसमें देशभर से लाखों प्रवासी कामगार आते हैं, रहते हैं।

उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2015 में तब के मूख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए दस रुपये में थाली की योजना प्रारंभ की थी। लेकिन यह योजना भी बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। महाराष्ट्र में भी कई बार कोशिशें हुईं, वहां शिव वडा पाव थाली शुरू की गई थी, वो हर चौक-चौराहे पर आज भी है तो, लेकिन उसमें मिलने वाला वडा पाव सामान्य कीमत में ही मिलता है। हाँ, बस शिव वडा पाव थाली के नाम पर उसे बेचने वाले रेहड़ी वालों को संरक्षण मिला रहता है। मालूम हो कि उद्घव ठाकरे सरकार ने इस थाली की शुरूआत की थी।

दिल्ली से ही सटे हरियाणा में भी राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण राशि से पूरे राज्य के 22 जिलों में सस्ती थाली की रसोई खोली, मगर लॉकडाउन के बाद से इनको शुरू नहीं करवाया जा सका। सरकार के श्रम विभाग ने 2018 में 20 रुपये की

लागत बाला खाना 10 रुपये में देना शुरू किया था। फरीदाबाद व पलवल के सामान्य अस्पताल में जनचेतना ट्रस्ट के तत्वावधान में 10 रुपये में भरपेट खाने की रसोई खोली गई, मगर ये भी अब नहीं चल रही हैं। इन दोनों रसोईयों का शुभारंभ हरियाणा के तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने किया था।

असल में ऐसी रसोई एक बार बड़े जोर-शोर से खोल दी जाती है, लेकिन बाद में इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता, या कहें कि ध्यान नहीं दिया जाता। एसजीओ का मकसद ठेका लेने तक ही होता है। राजस्थान में भी अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी। वसुंधरा राजे ने दिसंबर, 2016 में इसकी शुरुआत की थी। पांच से आठ रुपये में भरपेट खाना मिलता था। सत्ता बदली तो अन्नपूर्णा की जगह अब यह इंदिरा रसोई बन गई। क्या गरीब वर्ग सिर्फ वोट पाने तक ही संमित है गरीब के लिए चलाई जाने वाली जन आहार योजना तो चलाई ही जा सकती है। क्या पता आप दोबारा सत्ता में आ जाएं, कम से कम गरीब को रोटी तो मिलती रहे। दरअसल हमारे देश में मुँशी प्रेमचंद का गरीब जो आज भी हमारे समाज का बड़ा तबका है, उसे वोट बैंक की सेहत के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है, पर सिर्फ वोट पाने तक ही क्यों क्या उस शाली को सत्ता के मोह से आगे उत्पन्नी पौष्टिकता और जरूरत के लिए मिरंतर नहीं चलाया जा सकता सियासत की रोटियां तो सिकती ही रहती हैं, गरीब के पास तो सिर्फ निवाले की भूख है।



एकशन-थ्रिलर सीरिज के साथ डिजिटल दुनिया में एंट्री करेंगे निर्देशक रोहित शेट्टी

एकशन से भरी फिल्में निर्देशन रोहित शेट्टी की पहचान हैं और अब वे ऐसी ही एक वेब सीरिज के साथ डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने को तयार हैं। दिग्गज स्टॅटमेन एम बी शेट्टी के बेटे रोहित 'सिंघम', 'सिंघा', 'गोलमाल', 'चेत्रई एक्सप्रेस' और 'आल द बेर्स' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। शेट्टी एकशन-एडवेंचर शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' के साथ टीवी जगत में भी प्रवेश कर चुके हैं।

फिल्म की टीम के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई-को बताया, 'रोहित आज एपिसोड एकशन थ्रिलर वेब सीरिज बनाने वाले हैं। यह सत्य घटनाओं से प्रेरित होगी।' सीरिज के शीर्षक को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। रोहित फिल्हाल अपनी फिल्म 'सर्कस' को लेकर व्यस्त हैं। जिसमें वे अभिनेता रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक 'द कॉमेडी ऑफ एरस' पर आधारित है।

फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की सलमान खान से गुजारिश, थिएटर्स में रिलीज करे 'राधे योर मोर्स्ट वॉन्टेड भाई'

कोरोनावायरस महामारी की वजह से बड़े फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में दस्तक नहीं दे पा रखे हैं। भले ही सिनेमाघर खुल चुके हैं लेकिन लोग पहले की तरह थिएटर्स में पहुंच नहीं रहे हैं। इस दौरान कई बड़ी फिल्में ओटीटी प्लॉटफॉर्म पर रिलीज हुईं। अब फिल्म एपिजिवर्ट्स ने सलमान खान को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि उनकी फिल्म 'राधे' को ओटीटी की बजाय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए।

फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सलमान खान से गुजारिश की है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'राधे- योर मोर्स्ट वॉन्टेड भाई' को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला ना लें। वो अपनी फिल्म को सीधे ईद के मौके पर थिएटर्स में ही रिलीज करें। यही भाईजान की तरफ से उनके लिए सबसे बड़ी ईदी होगी।

फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी ने टिकटर पर लिखा है, डियर सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से यह गुजारिश है कि आप राधे को सीधे सिनेमाघरों में ही रिलीज करें। यही भाईजान की तरफ से उनके लिए सबसे बड़ी ईदी होगी।

राहत मिलेगी। हम राधे को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं।

सलमान खान की राधे इस समय में थिएटर्स के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। जो पहले कि तरह थिएटर्स में ऑडियंस को आकर्षित करें। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए राधे उन कुछ फिल्मों में से एक है जो सिनेमाघरों के लिए भाग्याली साबित हो सकती है।

बता दें कि फिल्म राधे में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी, रणवीर हुड्डा और जैकी शॉफ भी नजर आने वाले हैं खास बात तो यह है कि इस फिल्म में भी सलमान खान कॉपी की भूमिका में नजर आएंगे।

एकट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को मिली नया प्रोजेक्ट 'बुलबुल तरंग', पिछली कई फिल्में हुई पलौंप

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा निर्देशक श्री नारायण सिंह की फिल्म में मुख्य किरदार अदा करने जा रही हैं जिसका अंतरिम नाम 'बुलबुल तरंग' रखा गया है। सिंह की पुरानी फिल्मों 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', बड़ी गुल मीटर चालू (2018) की तरह ही फिल्म भी सच्ची घटना से प्रेरित होगी। फिल्म की टीम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई-से कहा, ''फिल्म में सोनाक्षी मुख्य भूमिका में हैं। इसमें राज बब्बर भी हैं। ताहिर राज भसीन भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। यह भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म होगी और पुराने जमाने के रीत-रिवाज के बारे में होगी।'' पहली बार सिंह और सोनाक्षी साथ काम करेंगे। फिल्म की शूटिंग मार्च-अप्रैल में शुरू होगी। सोनाक्षी 'भुज- द प्राइड ऑफ इंडिया' फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। इस फिल्म में अजय देवगन भी हैं और यह डिज्नी+हॉटस्टर पर रिलीज होगी।



'धूम 4' में नजर आ सकती हैं दीपिका पादुकोण, बनेंगी स्टाइलिश चोरनी!

यशराज फिल्म की एकशन फेंचाइजी 'धूम' की चौथी फिल्म का फैस बेस्ट्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा कारोल तो हमेशा फिल्म माना जाता है, लेकिन विलेन हर बार कोई दूसरा होता है। 'धूम 4' को लेकर सामने आई खबरों की माने तो इसमें दर्शकों को मेल चोर नहीं बल्कि फौमेल चोर नजर आएंगी।

खबरों के अनुसार यशराज बैनर ने 'धूम 4' में दीपिका पादुकोण को स्टाइलिश चोरनी के रूप में पेश करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और यशराज बैनर के बीच लगातार बालचीत जारी है और इस समय दीपिका पादुकोण शूटिंग डेट्स का अपने कैलेंडर में फिट करने की कोशिश कर रही हैं।

अगर सबकछु ठीक रहता है कि 'धूम 4' की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में कई बार एकशन किया है लेकिन माना जा रहा है कि 'धूम 4' का एकशन उनके फैस को भी चौकाकर रख देगा। इसमें वो हॉलीवुड स्टर के एकशन सीन्स फिल्माती दिखेंगी।

बता दें कि यशराज बैनर की 'धूम' सीरीज बॉलीवुड की पहली सफल फेंचाइजी है, जिसकी पहली तीनों फिल्मों को दर्शकों का खूब सारा ध्यान मिला है। अब तक दर्शक जॉन अब्राहम, रितिक रोशन और आमिर खान को इस फैंचाइजी में चोर का किरदार निभाते देख चुके हैं।

तापसी पन्नू ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह अक्सर खुद से जुड़ी हर अपडेट शेयर करती रहती हैं। उन्होंने अब अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए 'कॉर्किंगडेस' को लेकर दिलचस्प पोस्ट की है। तापसी पन्नू ने बताया कि सही 'कॉर्किंगडेस' क्या होता है? तापसी की यह पोस्ट फैस को बेहद पसंद आ रही है। तस्वीर में तापसी राडेड धूप का चश्मा पहने एक ग्रे रंग की ड्रेस में दिखाई दे रही है, जिसमें उनके बाल खुल हुए हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ कैशन लिखा, 'कॉर्किंगडेस' एक कर्मरे में नहीं चल रहा है यह सोचकर कि आप हर किसी से बहतर हैं। आप कभी किसी से पहली बार मिल कर उससे खुद की तुलना न करें। हैप्पी सेड!' तापसी की पोस्ट पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। वर्क फंट की बात करें तो तापसी पन्नू फिल्म 'रेशम रॉकेट' में नजर आएंगी। फिल्म में वह एक धावक की भूमिका में है। इसके अलावा तापसी की आने वाली फिल्म 'लूप लेप्टा' की शूटिंग भी जोरें पर चल रही है। फिल्म में ताहिर राज भसीन भी अहम किरदार में हैं।



'कुली नंबर 1' की आलोचना करने वालों को वरुण धवन ने दिया जवाब, बोले - मुझे फर्क नहीं पड़ता...

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'कुली नंबर 1' पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इसे ओटीटी लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। फिल्म का फैस बेस्ट्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज होने के बाद इसे काफी निगेटिव फीडबैक मिला। सोशल मीडिया पर कुली नंबर 1 को लेकर फैसी मिलने लगे, वरुण के सोन्स का मजाक उड़ाया गया और सारा की एकिंग पर भी तंज कर से गए। हाल ही में फिल्म की आलोचना को लेकर वरुण धवन से बातचीत में गई, जिस पर एक्टर ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज तो हिट नहीं हो सकती है।

एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में वरुण धवन ने कहा, चीजें करना मुश्किल होता है। जिन्हीं से भी कई बड़ी होती हैं। उन चीजों के प्रति आपके अंदर सहनशीलता होनी जरूरी होती है। मैं एंजॉय करता हूं। मेरे लिए एक फिल्म बनाना मतलब सभी को ऐजी करना होता है। जनता का रिएक्शन मेरे लिए काफी मायने रखता है।

वरुण आगे कहते हैं, मैं फैक हो सकता हूं और कूल बनने की भी कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरी फिल्म ओटीटी पर है। यह मेरी ऑडियंस है और मैं इसी के लिए काम करता हूं। जो कोई कहता है कि मैं कूल नहीं हूं, क्योंकि मैं कई खाराब फिल्में भी करता हूं तो ठीक है मैं कूल नहीं हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता है।

बता दें कि फिल्म कुली नंबर 1 का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है। इसमें वरुण धवन और सारा अली खान रोमांस करते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी पुरानी कुली नंबर 1



